ARYAVART SHODH VIKAS PATRIKA
ISSN No.: 2347-2944, RNI:UPBIL04292,REG.No.:561/2013-14 Vol.-I, No.-1, PP-90-92, YEAR 2013

वैश्वीकरण एवं अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

❑ डॉ0 सुनील कुमार सुरोथिया

वैश्वीकरण की प्रक्रिया आधुनिकीकरण की वैचारिकी का ही रूप है। जिनका प्रयोग विश्व की नजदीकियाँ बढ़ने, मानवता के प्रति प्रेम, सम्पन्न राष्ट्रों की उदारता और गरीब राष्ट्रों के हित चिन्तन में उनके बेहाल होने के लुभावने सन्दर्भों में हो रहा है। इसमें मानवता का भाव न होकर भोगवादी दर्शन क्रियाशील हैं इसमें मुख्य ध्येय अधिकतम् सुखोपभोग के साधन एकत्रित करना है। यह पाश्चात्य संस्कृति पर आधारित है। सच तो यह है कि वैश्वीकरण वर्तमान समय का यथार्थ है। जिसके प्रभाव से कोई भी राष्ट्र बच नहीं सकता, क्योंकि तकनीकी, वित्तीय एवं बदली हुई प्रायोगिक परिस्थितियों में वैश्वीकरण की प्रक्रिया को रोक पाना सम्भव नहीं है। वस्तुतः वैश्वीकरण के साथ आँख बन्द करके चलने से गरीब नागरिकों को हित चिन्तन नहीं किया जा सकता। आज भारत में अनाज का अतिरिक्त भण्डार है, हमारे पास प्रशिक्षित मानव संसाधन, भौगोलिक संसाधन तथा जैव विविधता के साथ वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के लिए सक्षम आधारभूत ढाँचा उपलब्ध है हम अन्तरिक्ष विज्ञान, तकनीक के क्षेत्र में निरन्तर नवीन अनुसन्धान व खोज कर रहे है यदि हम अपने सामाजिक आर्थिक विकास को तीव्र गति देना चाहते है तो हमें अपनी खोजों तथा उपलब्धियों से सर्वोत्तम लाभ प्राप्त करना होगा, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हमें भूमण्डलीकरण के साथ चलना होगा, क्योंकि तभी हम अपने लिए उदार, नियंत्रित, सुस्पष्ट, प्रमाणिक रूप से पारदर्शी तथा अनिश्चितताओं से मुक्त विश्व बाजार प्राप्त कर सकते है, जैसा कि वर्तमान में चीन विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है, एक तरफ हमारे पास पर्याप्त संसाधन हैं तथा दूसरी तरफ देश में गरीबी, बेरोजगारी है इस समस्या के समाधान के लिए हम भूमण्डलीकरण के तहत पर्याप्त मात्रा में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को आकर्षित कर अपना सामाजिक आर्थिक विकास कर सकते हैं।

वर्तमान काल वैश्वीकरण का युग माना जा रहा है। इसकी शुरूआत 15वीं शताब्दी से प्रारम्भ हुई और निरन्तर यह विकसित प्रक्रिया में है। 20वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में वैश्वीकरण संयुक्त राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विकसित देशों के सहयोग से मजबूत हुआ। आर्थिक एवं व्यापारिक नीतियों के लिए डंकल प्रस्ताव के चलते गैट का निर्माण हुआ। गैट के अन्तर्गत विश्व व्यापार संगठन निर्मित हुआ। क्रमबद्धता और निरन्तरता के परिवेश में वैश्वीकरण के प्राविधान बढ़ते जा रहे हैं। इसकी पकड़ में सम्पूर्ण विश्व है। भारत में इसके प्रभाव पड़ने शुरू हो गये हैं। आयात–निर्यात, पूँजी विनियोजन, कीमत उत्पादन की मात्रा, शिक्षा चिकित्सा व्यापार और कृषि सभी क्षेत्र विश्व व्यापार संघठन की परिधि में प्रतिबन्धित हो चुके हैं।

इस आर्थिक अवधारणा के तहत आर्थिक सम्बृद्धि की जिस किस्म को बढ़ावा दिया जा रहा है; उसमें देशों के बीच और उनके अन्दर आर्थिक विषमता बढ़ी है। इस लक्ष्य को लन्दन स्कूल ऑफ इकोनामिक्स के प्रो0 राबर्ट ने अपने कुछ समय पहले प्रकाशित एक लेख में रेखांकित किया है। इनके अनुसार आय का भूमण्डलीय वितरण दिनों–दिन अधिकाधिक विषम होता जा रहा है। ऐसा उन्होंने कुछ

असि0 प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान,राजकीय डिग्री कॉलेज, मेहरौनी, ललितपुर, झांसी (उ0प्र0), भारत

शोधकर्त्ताओं के आधार पर कहा है। शोधकर्त्ताओं ने यह तथ्य उजागर किया है कि पिछले कई दशक से दुनिया के देशों के बीच आय का वितरण असमान होता जा रहा है। इस असमानता में 1980 के दशक के बाद तेजी से वृद्धि हुई है। इन शोध कार्यों का हवाला प्रो0 वेडे ने दिया है, उनमें एक है ब्राको मिलानो विच जो विश्व बैंक से जुड़े रहे है और उन्होंने विश्व बैंक के आँकड़ों को अपना आधार बनाया। ब्राकों मिलानों बिच ने इसके प्रभाव के एक पक्ष आर्थिक विषमता को ज्ञात करने में सफलता प्राप्त की है। इसका प्रभाव अन्य क्षेत्रों सामाजिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक रूप से कितना भयावह होगा, इसका अनुमान इसी में लगाया जा सकता है।

1960 ई0 के पूर्व लगभग हजारों वर्ष तक भारत में स्थिर अर्थव्यवस्था चलन में रही है। पिछले दो सौ वर्षों के पूर्व लगभग सम्पूर्ण विश्व में स्थिर अर्थव्यवस्था का प्रचलन रहा है। यद्यपि भाषाओं, वेशभूषा व धार्मिक कर्मकाण्ड में भिन्नता रहते हुए भी जीविकोपार्जन के साधनों में आर्थिक समानताएँ रही। लेकिन औद्योगिक क्रान्ति के हो जाने से गत्यात्मक अर्थव्यवस्था ;क्लदंउपब म्बवदवउलद्ध का समावेश भारत में हुआ। संयोग यह रहा कि जिस देश में सर्वप्रथम औद्योगिक क्रान्ति विश्व में हुई उसी देश ने भारत का शासन अपने हाथ में संभाला। औद्योगिक क्रान्ति और विदेशी शासन के चलते भारतीय शिक्षा, संस्कृति व सामाजिक संरचना बुरी तरह प्रभावित हुई। इस स्थिति से उबरने के लिए 20वीं सदी के प्रारम्भ में स्वदेशी आन्दोलन का प्रारम्भ भारत में हुआ।

20वीं सदी में प्रत्येक चीज का वैश्वीकरण हुआ है। सैन्य शक्ति के साथ–साथ आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों का अन्तर्राष्ट्रीयकरण हुआ है। कोई भी देश किसी चीज का अपनी अर्थव्यवस्था और स्रोतों से उत्पादन करता है, किन्तु उसका लाभ पूरा विश्व उठाने लगा है। लोगों की पहुँच उन्नत विचारों तक आसान हुई। वैश्वीकरण से एक तरफ तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए खाद्यान्न, चिकित्सा, शिक्षा आदि की सर्वसुलभ की दृष्टि से लाभ हुआ है, तो दूसरी तरफ सामाजिक संरचना, सास्कृतिक विरासत और मानवता का संकट उत्पन्न हुआ है। वैज्ञानिकों और अर्थशास्त्रियों का मानना है कि आज वैज्ञानिक और सूचना क्रान्ति के युग में स्वदेशी के नाम पर पीछे की ओर देखना यथार्थ से विमुख होना है।

वैश्वीकरण के परिणामस्वरूप वर्तमान विश्व विकसित, विकासोन्मुख और अविकसित क्षेत्रों में विभक्त हैं विकासोन्मुख और अविकसित देश विकसित देशों के समक्ष प्रतिस्पर्धा में कमजोर है। ऐसी ही स्थिति में भारत भी है। विभिन्न देशों के बीच जीवन स्तर में पर्याप्त अन्तराल हैं विकसित देशों की संस्कृतियों उपभोक्तावादी दृष्टिकोण से संचालित है। ॅण्ज्ण्व् के चलते हुए पिछड़े देशों के पर्यावरण तथा श्रम पर कठिन परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई। हमारे देश में बेकारी की भयंकर समस्या है। उत्पादन के बढ़े पैमाने के कारण बेरोजगारी का निवारण संभव नहीं है। यहाँ यह विचारणीय विषय है कि ऐसी स्थिति में दूर दृष्टि और स्थानीय दृष्टि के बीच किस प्रकार के समीकरण की रचना हो जिसके चलते हुए भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर बचाया जा सके और वैश्वीकरण के बढ़ रहे कमद के साथ ताल–मेल बैठाया जा सके।

हमारे ऋषि–मुनियों की भावना–'कृण्वन्तो विश्वभार्यम' तथा 'सर्व भूते हितरतः' सारी दुनिया को श्रेष्ठ बनाने का स्वप्न रही है। यह भारतीय ऋषियों ने वसुधैव कुटुम्बकम् की सार्थकता के लिए उद्घोष किया था। यही भारतीय वैश्वीकरण की संकल्पना और इसी को वैश्वीकरण के सन्दर्भ में हमारी भूमिका निर्धारित करती हैं भारत की महानता और उसकी पहचान उसकी प्राचीन संस्कृति के कारण है। यहाँ योग को नहीं त्याग और संयम को महत्व दिया गया है। 'परहित सरिस धर्म नहि भाई'। पश्चिम में सब कुछ अपने लिए है; व्यक्ति परक है। योग ही जीवन का प्रधान तत्व है।

वैश्वीकरण की सहायता से भारत में सामाजिक आर्थिक स्थिरता, संरचनात्मक सुधार स्वावलम्बी आत्मनिर्भर, उत्पादन क्षमता का पूर्ण विदोहन, न्यूनतम लागत पर अधिकतम तथा श्रेष्ठ उत्पादन, रोजगार, विश्व अर्थव्यवस्था में अपना स्थायी स्थान प्राप्त कर सकता है, इस वैश्वीकरण के तहत हम अपनी अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा तथा गति प्रदान कर सकते है, इससे बाहर रहकर नहीं, आवश्यकता सिर्फ इस बात की है कि हमारी दृष्टि में हमारे लक्ष्य स्पस्ट हो, लक्ष्य प्राप्ति का मार्ग बाधा रहित रहे, यदि बाधा आती है तो उसका प्रभावी एवं हितकारी समाधान करें जैसा कि ब्राजील ने स्विस कम्पनी रोशे को एड्स के लिए प्रयुक्त वेलफिनाविर औषधि को 40 प्रतिशत कम कीमत पर बेचने को मजबूर करके किया, इतना होने पर भी यदि आपका हित नहीं होता है तो आप 6 माह के नोटिस पर विश्व व्यापार संगठन से बाहर आने के लिए स्वतंत्र हैं।

अतः स्पष्ट है कि वर्तमान में अन्य विकासोन्मुखी समाजों के समान ही भारत में भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया के नकारात्मक परिणाम इसके सकारात्मक परिणाम की अपेक्षा कहीं अधिक प्रबल है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची –

1. Mishra P. and Prusty R., Indian Insutry and Liberalised Rolicy Regime, Yojana, Vol. 45, Nov. 2001
2. Malik, M.S., Globlization and Human Resource Development Yojana, March, 2001
3. Robertson R., Globalisation: Social theory and Global Culture, London Sage Publication, 1992
4. Ross, G., Labour versus globlisation, Annuals of the American Acaemy of Political Social Sciences, Vol. 570 (July) P.P.M. and 78 as abstracted by the American Resource Centre, New Delhi, 2000
5. Rosenau, J., The Study of Global Interdependence, Princeton University, 1990
6. Yogendra Singh, Culture Change in India, Rawat, Jaipur, 2000.
7. ए. अहमद सिद्दकी : उदारीकरण और श्रम सुधार, योजना, योजना भवन, संसद मार्ग, नई दिल्ली, मई 2003
8. पाण्डेय, सत्यव्रत, अध्यक्षीय सम्बोधन, सत्रहवाँ उत्तर प्रदेश समाजशास्त्र सम्मेलन, म0गां0 काशी विद्यापीठ, वाराणसी, 15–16 नवम्बर, 2003
9. श्रीवास्तव, डॉ0 राजीव कुमार, वैश्वीकरण एवं समाज, वैभव लक्ष्मी प्रकाशन, वाराणसी, संस्करण–प्रथम, 2012–2013

*****